

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1.अपील संख्या 1647 / 2010 / भीलवाड़ा

मैसर्स डायनेमिक इंजीनियर्स  
एण्ड कन्सलटेंट्स, भीलवाड़ा

.....अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स,  
भीलवाड़ा

.....प्रत्यर्थी

2.अपील संख्या 2273 / 2010 / भीलवाड़ा

वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स,  
भीलवाड़ा

.....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स डायनेमिक इंजीनियर्स  
एण्ड कन्सलटेंट्स, भीलवाड़ा

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम.पी.शर्मा

अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री आर.के.अजमेरा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 03.07.2017

निर्णय

उपयुक्त दोनों अपीलों में से प्रथम अपील अपीलार्थी द्वारा एवं द्वितीय अपील विभाग की ओर से उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, भीलवाड़ा (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 71/सीएसटी/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 09.06.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाड़ा (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.05.2004 को राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 28 के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 के लिए पारित अस्थाई कर निर्धारण आदेश में रु. 1,31,69,679/- के सप्लाई एण्ड फिक्सिंग आप इलेक्ट्रिकल एसेसरीज के कार्यों पर 4प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क रु. 5,26,787/- एवं इस पर सरचार्ज 12 प्रतिशत की दर से रु. 63,214/- कुल रु. 5,90,001/- आरोपित किया। उक्त पारित आदेश में संशोधन हेतु संशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सशक्त अधिकारी ने संशोधन प्रार्थना पत्र अस्वीकार करते हुए आदेश दिनांक 22.12.2007 पारित किया। उक्त संशोधित आदेश दिनांक 22.12.2007 से



असन्तुष्ट होकर अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने यह निष्कर्ष दिया कि यदि बिजली का सामान सिविल वर्ककमें ज्यादा लगता है तो भी सिविल वर्क ही रहेगा इसलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 3 प्रतिशत की दर से निर्धारित कर राशि रु. 3,95,090/- व उस पर आरोपित सरचार्ज रु. 47,410/- कुल रु. 4,42,500/- को अपास्त करते हुए कुल रु.1,31,69,679/-पर एक प्रतिशत की दर से रु. 1,31,697/- व सरचार्ज रु. 15,803/- कुल रु. 1,47,500/- को यथावत रखा है। अपीलीय अधिकारी द्वारा ई.सी.फीस व मजदूरी की राशि कम करने के पश्चात ही ई. सी.फीस लगाने के बिन्दु पर बिन्दुओं पर अपील अस्वीकार की गई है। अपीलीय अधिकारी में अपास्त की गई राशियों के सम्बन्ध में विभाग की ओर से एवं अपील जिन बिन्दुओं पर अस्वीकार की गई उसके विरुद्ध अपीलार्थी की ओर से ये दोनों अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि ई.सी.पर आधारित कुल प्राप्तियों रु. 1,31,69,679/-थी। इन प्राप्तियों में राज्य के बाहर से खरीद की गई राशि व मजदूरी की राशि भी सम्मिलित थी। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने अनुचित रूप से राज्य के बाहर से की गई खरीद राशि व मजदूरी राशि पर आरोपित कर मुक्त शुल्क को यथावत रखा है, जो अनुचित है। उन्होंने उक्त कथन के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मैसर्स गैनन एण्ड डंकरले कम्पनी लिमिटेड को उद्धृत किया साथ ही उन्होंने मैसर्स त्रिवेणी इन्जीरियरिंग 9 सेल्सटैक्स टूडे 163 को भी उद्धृत किया। उनका यह भी कथन है कि राज्य के बाहर से आयातित माल को संविदा कार्य में निष्पादित किये जाने से राज्य के अन्दर कर देतयय नहीं बनती है इसलिए इस पर आरोपित कर मुक्ति शुल्क अपास्त किया जाये। उनका यह भी कथन है कि अधिनियम की धारा 2(38) में विक्रय की परिभाषा तथा धारा 2(42) में कर योग्य आवर्त को परिभाषित किया गया है। उनका कथन है कि संविदा कार्य में कर योग्य आवर्त को निर्धारित करने के लिए संविदा कार्य के निष्पादन में मजदूरी की राशि को कुल आवर्त में कम किये जाने का प्रावधान है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार कर विभाग की अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का पुरजोर समर्थन किया एवं तर्क दिया कि अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 में ई.सी. शुल्क सकल प्राप्तियों पर है न कि पण्यावर्त पर। अतः कर मुक्ति प्रमाण पत्र संविदा में प्रयुक्त माल मय समस्त प्राप्तियों के (मजदूरी सहित) पर आरोपित किया जाना विधिनुकूल है। उनका कथन है कि शास्ति पत्रावली के पेज पर उपलब्ध फार्म एस टी 2 के कालम संख्या 9 में **Description of the Contract & place of execution of work** में स्पष्ट रूप से अंकित **work order for work of Pumping Station and Switchgard at Bhalutibba (RPSD) on lump sum Turnkey basis.** इसी प्रकार पत्रावली के पेज संख्या 10 पर उपलब्ध पत्र में

६



Sub. work order for work of Pumping Station and Switchgard at Bhalutibba (RPSB) on lump sum Turnkey basis अंकित किया गया है, जो सिविल वर्क की श्रेणी में नहीं आता है इसलिए उक्त वर्क आर्डर को सिविल का आर्डर मानकर अपीलीय अधिकारी द्वारा आरोपित कर मुक्ति शुल्क व सरचार्ज रू. 4,42,500/-को अपास्त किया जाना अनुचित है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर विभाग की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार कर व्यवहारी की अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड एव विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया गया। शास्ति पत्रावली अवलोकन से ज्ञात होता है कि पत्रावली के के पेज पर उपलब्ध फार्म एस टी 2 के कालम संख्या 9 में Description of the Contract & place of execution of work में स्पष्ट रूप से अंकित work order for work of Pumping Station and Switchgard at Bhalutibba (RPSD) on lump sum Turnkey basis. इसी प्रकार पत्रावली के पेज संख्या 10 पर उपलब्ध पत्र में Sub. work order for work of Pumping Station and Switchgard at Bhalutibba (RPSB) on lump sum Turnkey basis अंकित किया गया है, जो सिविल वर्क की श्रेणी में नहीं आता है इसलिए उक्त वर्क आर्डर को सिविल का आर्डर मानकर अपीलीय अधिकारी द्वारा आरोपित कर मुक्ति शुल्क व सरचार्ज रू. 4,42,500/-को अपास्त किया जाना अनुचित है। कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त कार्यो को अधिसूचना के आईटम नम्बर 3 से कवर्ड मानते हुए कर मुक्ति शुल्क आरोपित की है। अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 निम्न प्रकार है :-

Item No.	Description of work contract	Rate of exemption fee % of the total value of the contract
1	2	3
1.	Works contracts relating to dyeing, printing, processing and similar activities.	0.25 %
2.	Works contracts relating to buildings, roads, bridges, dams, canals, sewerages system.	1.50 %
3.	works contract relating to installation of plants & machinery including PSPO, water treatment plant, laying pipeline with material.	2.25 %
4.	Any other kind of works contract not covered by item No.1, 2 and 3.	3.00 %

4



उपरोक्त अधिसूचना के आईटम संख्या 2 में Works contracts relating to buildings, roads, bridges, dams, canals, sewerages system. आदि अंकित है, जबकि फार्म एस टी 2 के कालम संख्या 9 में Description of the Contract & place of execution of work में स्पष्ट रूप से अंकित work order for work of Pumping Station and Switchgard at Bhalutibba (RPSD) on lump sum Turnkey basis. इसी प्रकार पत्रावली के पेज संख्या 10 पर उपलब्ध पत्र में Sub. work order for work of Pumping Station and Switchgard at Bhalutibba (RPSB) on lump sum Turnkey basis अंकित किया गया है, जो सिविल वर्क की श्रेणी में नहीं आता है। इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने उपरोक्त अधिसूचना में कर दर सम्बन्धी सूची के आईटम नम्बर 4 से कवर्ड मानकर कर मुक्ति शुल्क आरोपित किया है, जिसको अपीलीय अधिकारी ने अनुचित रूप से अपास्त किया है। अतः इस बिन्दु पर अपीलीय अधिकारीके आदेश को अपास्त करते हुए कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को बहाल किया जाता है।

जहां तक मजदूरी की राशि कम करनेके पश्चात ही ई.सी.फीस आरोपित करने का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में कर बोर्ड द्वारा अपील 1713 / 2012 / भीलवाडा (कुल 13 अपीलों) मैसर्स भौरीलाल मोहन लाल, भीलवाडा वगौरह बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाडा निर्णय दिनांक 07.09.2015 का बहस के दौरान हवाला दिया गया है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय स्टेट आफ केरला बनाम बिल्डर्स एसोसियेशन आफ इण्डिया (1997) 104 एस टी सी 134 को उद्धरित करते हुए इस बिन्दु पर निष्कर्ष दिया है, जो निम्न प्रकार है

“.....The first feature to be noticed is that the alternate method of taxation provided by sub-section (7) of (7A) of section 7 is optional. The sub-sections expressly provide that the method of taxation provided thereunder is applicable only to a contractor who elects to be governed by the said alternate method of taxation. There is no compulsion upon any contractor to opt for the method of taxation provided by sub-section (7) or sub section (7A). It is wholly within the choice and pleasure of the contractor. If he thinks it is beneficial for him to so opt, he will opt; otherwise, he will be governed by the normal method of taxation provided by section (5)(1)(iv). Sub-section (8) provides that the option to come under sub-section (7) or (7A) has to be exercised by the contractor 'either by an express provision in the agreement for the contract or by an application to the assessing authority, to permit him to pay the tax in accordance with any of the said sub-sections'. **In these circumstances, it is evident that a contractor who had not opted to this alternate method of taxation cannot complain against the said sub sections,**

↓



for he is in no way affected by them. Nor can the contractor who has opted to the said alternate method of taxation, complain. Having voluntarily, and with the full knowledge of the features of the alternate method of taxation, opted to be governed by it, a contractor cannot be heard to question the validity of the relevant sub-sections or the rules... The impugned sub-sections have evolved a convenient, hassle-free and simple method of assessment just as the system of levy of entertainment tax on the gross collection capacity of the cinema theatres. By opting to this alternate method, the contractor saves himself the botheration of book-keeping, assessment, appeals and all that it means. It is not necessary to enquire and determine the extent or value of goods which have been transferred in the course of execution of a works contract, the rate applicable to them and so on. For example, under sub-section (7), the contractor pays two per cent of the total value of the contract by way of tax and he is done with all the abovementioned botheration. The rate of two per cent prescribed by sub-section (7) is far lower than the rates in First, second and Fifth Schedules referred to in section 5(1)(iv)(a). In short, sub-section (7) and (7A) evolve a rough and ready method of assessment of tax and leave it to the contractor either to opt to it or be governed by the normal method. It is only an alternative method of ascertaining the tax payable, which may be availed of by a contractor if he thinks it advantageous to him... The Constitution does not preclude the Legislature from evolving such alternate, simplified and hassle-free method of assessment of tax payable, making it optional for the assessee. The object of sub-sections (7) and (7A) is the same as that of section 5(1)(iv); it is only that they follow a different route to arrive at the same destination of tax liability which may sometimes be in the interest of both the Revenue and the assessee. It must also be remembered that in the field of taxation, the Legislature must be allowed greater 'play in the joints', as it is called."

उपरोक्त दी गयी व्यवस्थाओं के प्रकाश में यह निष्कर्षित किया जाता है कि प्रश्न का विकल्प लिये जाने के बाद अपीलार्थी व्यवहारीगण प्रश्न से भिन्न करारोपण के तरीके से करारोपण की मांग करते हुए लेबर राशि को घटाने की मांग नहीं कर सकते हैं। प्रश्न राशि सम्पूर्ण प्राप्तियों Total Receipts / Total Turnover पर विहित मुक्ति शुल्क की दर से ही मुक्ति शुल्क राशि देय होगी।"

संकर्म संविदा के तहत कार्य निष्पादन करने वाले ठेकेदारों के लिये राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.12(63)एफडी / टैक्स / 2005-80 दिनांक 11.8.2006 के द्वारा संकर्म संविदा में कार्यरत पंजीकृत व्यवहारियों को उनके द्वारा निष्पादित किये जाने वाले संकर्म संविदा में माल सम्पत्ति हस्तान्तरण पर कर उद्ग्रहण करने से



अधिसूचना में विहित शर्तों के आधार पर कर से मुक्ति दी गई है। व्यवहारी ठेकेदार के द्वारा कर दायित्व का भुगतान मुक्ति शुल्क के रूप में किये जाने का विकल्प लिये जाने पर मुक्ति शुल्क की राशि इस हेतु घोषित ठेके की राशि पर ही अधिसूचना में विहित दर से मुक्ति शुल्क उद्ग्रहणीय है। व्यवहारी द्वारा विकल्प लिये जाने के पश्चात उसमें शामिल मजदूरी राशि को घटाने का तर्क देना अधिसूचना के तहत अनुज्ञेय नहीं है।

अधिसूचना क्रमांक एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005-80 दिनांक 11.8.2006 का बिन्दु संख्या 5 एवं तालिका के कॉलम 1, 2 व 3 निम्न प्रकार है :-

In exercise of the power conferred by sub-section (3) of section 8 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, **hereby exempts from payment of tax the registered dealers engaged in execution of works contracts leviable on the transfer of property in goods** (Whether as goods or in some other form) involved in the execution of works contract(s) **subject to the following conditions, namely:-**

(5) that such contractor shall pay exemption fee at the rate specified in Column 3 of the list given below in the following manner :-

(i) where an awarder is a Department of any Government, a Corporation, a public undertaking, a co-operative society, a local body, a statutory body, an autonomous body, a trust or a private or public limited company, an amount calculated at the rate as specified in column no.3 of the list given below shall be deducted by such awarder from each bill of payment to be made in any manner to such contractor and all the provisions of payment of tax provided in the Act or the rules made there under for contractors shall *mutatis mutandis* apply. In case the contractor has already received some payments for execution of works contract from the awarder before filing application, he shall enclose proof of payment/deduction of notified exemption fee on such payments, along with interest, if any, up to the date of filling of application, under this notification;

(ii) where the awarder is not covered under sub-clause (i) above, the contractor shall be required to make payment of exemption fee in equal monthly installments in a period not exceeding the period of contract from the date of filing of application. In case the contractor has already received some payments for execution of works contract from the awarder, he shall enclose proof of payment of notified

↓




exemption fee on such payment along with interest up to the date of filing of application, under this notification;

- (iii) the amount already deducted by the awarder in lieu of tax from bills of payments to the dealer before the issuance of this notification shall be adjusted against the exemption fee;

प्रकरण के उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आधार पर अपीलीय अधिकारी द्वारा कर मुक्ति शुल्क की 3 प्रतिशत से निर्धारित कर राशि रू. 3,95,090/- तथा इस पर आरोपित सरचार्ज रू. 47,410/- कुल रू. 4,42,500/- को अपास्त किये जाने के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारीके आदेश को अपास्त किया जाकर इस बिन्दु पर विभाग की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकारकी जाती है एवं ई.सी.फीस में मजदूरी की राशि कम किये जाने के बिन्दु पर व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत की गई अपल अस्वीकार की जाती है।

फलतः व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत की गई अपील अस्वीकारकी जाती है एवं विभाग की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया ।

  
(मदन लाल मालवीय)  
सदस्य